श्री सुखराम : वैसे तो वर्मा जी अंग्रेजी जानते हैं, मैंने वह अंग्रेजी में पढ़ा और यह बताया है कि क्या कारण है, किस वजह से प्रोडक्शन में कमी हुई । मैंने उसमें कहा कि गन्ने में जो अरली फ्लावरिंग हो गई और मैच्यूरिटी अरली हो गई, उसके बारे में हमने टीमें भेजी थीं और मालूमात किया था । अगर आपकी तसल्ली न हो तो आप चेयरमैन साहब की इजाजत से फिर पूछ लीजिये । खासतौर पर यू० पी० में गुड़ और खंडसारी की कीमत कुछ ज्यादा थी और इस वास्ते गुड़ और खंडसारी के लिए केन का डाइवर्शन था । नार्मल लेवल पर उसका डाइवर्शन हुआ है । अगर ऐसा न होता तो पिछले वर्ष शुगर का जो उत्पादन था वह 91.10 लाख टन था, तो यह पिछला इतना न बढ़ता । एक रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है । अब यह सीजन की वेरीएशन की वजह से हुआ है ।

उन्होंने दूसरा प्रश्न यह किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला । किसानों को दो किस्म की कीमत निधारित की जाती है--एस० एम० की है । एक तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है । वह पहले साढ़े 18 रुपये था और अब 19.50 रुपये कर दिया है और अगले सीजन के लिए 20 रुपये कर दिया है और जो स्टेट एडवाइज प्राइस है वह ज्यादा है । यह इसलिये है कि जिससे किसानों को इंसेंटिव प्राइस मिलना चाहिए और वह इंसेंटिव प्राइस उनको मिलता है । इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि शायद कीमतें बढ़ी हैं । पिछले साल जो फ्री सेल की रिलीज थी, वह मार्च से जुलाई तक 22.90 लाख थी जब कि इस वर्ष हमने 24.60 लाख फ्री सेल में रिलीज की है । 2 लाख टन ज्यादा रिलीज किया । इससे कीमतें नहीं बढ़नी चाहिये थीं । मगर उसके कारण हैं । हमने होर्डिंग के बारे में स्टेप्स उठाये हैं और स्टेट्स गवर्नमेंट को लिखा है कि वे देखें कि होर्डिंग कहीं न हो और हमने जो पीरियड था उसको भी रड्यूस किया है और जो भी इस संबंध में मुनासिब कदम हैं वे उठाये हैं । खंडसारी के बारे में कभी नियंत्रण नहीं था । मगर इस वर्ष खंडसारी के बारे में स्टेट्स गवर्नमेंट को कहा गया कि अपना स्टाक डिक्लेयर करें कि कितने परसेंट के हिसाब से खंडसारी लोगों को मिले । मगर कुछ ऐसी बातें प्रेस में आईं कि शायद स्मगलिंग बंगलादेश और नेपाल को भी हो रहा है । उसके बारे में भी संबंधित सरकारों को लिखा और होम मिनिस्ट्री को भी लिखा कि इस स्मगलिंग को रोका जाये । मैं माननीय सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास सफिसिएन्ट स्टाक है, मुनासिब स्टाक है और अगले आने वाले सीजन तक हम लेवी और फ्री सेल की जो हमारी रिलीज है उसका ठीक रखेंगे और मुनासिब दाम पर देंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन किसानों को तो लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया । चीनी का उत्पादन भी नहीं बढ़ा है । जैसा लाभकारी मूल्य खंडसारी और गुड़ पर दिया गया है वैसा नहीं दिया गया है ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 63.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, is this question over?

MR. CHAIRMAN: Forty Minutes are over...*(Interruption)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Please allow us. Sir, West Bengal sugar quota.....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have called the next question.

Launching of a New Scheme for the Urban Poor

*63. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to launch a new scheme for the urban poor;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether the said scheme is likely to be implemented during the current financial year; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (d) The Government attaches high importance to formulation of schemes for alleviation of urban poverty. The scope and modalities of such schemes have to be worked out in consultation with various Departments and agencies concerned. The salient features of the scheme and the time schedule will be determined only thereafter.

SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Sir, in urban areas in our country, more than 30 per cent poor people are deprived of electricity. More than 40 per cent people have no toilet facility and many of them are residing in slum areas. The urban bodies are unable to solve these problems due to paucity of funds. So, I want to know from the hon. Minister whether the Government will introduce a scheme like Jawahar Rozgar Yojna by which these problems of the urban poor like provision of new electrified houses and toilets can be solved.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था कि कोई न्यू स्कीम क्या अरबन पुवर्स के लिये है । जनरल वे में उन्होंने नई स्कीम्स की बात कही थी । मेरी राय में उनकी मंशा यह थी कि जो अनइम्पलाईड पुवर हैं, वे जानना चाहते थे कि क्या उनके लिये कोई स्कीम हैं । लेकिन उन्होंने जो अभी बात की है वह गंदी बस्तियों में रहने वालों, स्लम एरियाज में रहने वालों की और उनके लिये लेट्रीन, बाथ रूम और छोटे घर के बारे में उन्होंने पूछी हैं । बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जो अभी भी शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं । लेकिन यह बात सही है कि जितनी इम्पार्टेंस शहरों की पावर्टी को कम करने के लिए दी गई थी उतना वह हो नहीं पाया । सबसे पहले जो 1978 और 1983 में प्लानिंग कमीशन ने पावर्टी के बारे में अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने जो रेकमेंडेशन न्यूट्रेशनल रेक्वायरमेंट, वैलरीज की की है उसके बेसिस पर पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उसको बेस माना था । उसके बाद पहली मर्तबा सेवथ प्लान में इसकी तरफ खास तवज्जह दी गई और प्लानिंग कमीशन ने एंटी पावर्टी प्रोग्राम के तरफ इंडीवेट किया । इसके अलावा माननीय, आपको मालूम ही है कि नेशनल कमीशन आन अरबनाइजेशन ने भी इसकी पहली मर्तबा इनडेप्थ स्टडी की है । अरबन पावर्टी को दूर करने के लिये इस वक्त सेल्फ इम्पलाइमेंट स्कीम चल रही है और जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको 5 हजार रुपया लोन दिया जाता है जिससे कि वे अपना काम शुरू कर सकें । जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिये भी स्कीमें चल रही हैं । जहां तक हाउसिंग का सवाल है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इसके लिये काफी स्कीमें चल रही हैं । स्टेट गवर्नमेंटस के थ्रू खास तौर से एकानामीकली वीकर सेक्शन के लिये हुडको की तरफ से लोन भी दिया जाता है । जो अरबन एरियाज हैं उसमें भी और जो रूरल एरियाज हैं उसमें भी ये स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से चलाई जा रही हैं । स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो फार्म्यूलेट करके देती हैं उसके तहत हम देते हैं और यह कहा जा सकता है कि कुछ स्टेट्स में ये स्कीमें बड़े अच्छे ढंग से चल रही हैं ।

श्री पथंतनेनि उपेन्द्र : कौन सी स्टेट्स हैं, नाम बताइये ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं बताऊंगी अभी ।

जो स्लम एरियाज की बात है इनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट आफ स्लम एरियाज इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बजट होता है और उसमें 350 रुपया पर कैपिटा के हिसाब से उनकी हालत को सुधारने के लिये देते हैं ।

SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU : My second supplementary is, the poor labourers of the villages are migrating to the urban areas and residing there in a very pitiable conditions and going without any houses, food and clothes. Therefore, I would like to know from the honourable Minister whether these problems can be solved by the scheme which will be introduced.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, यह बिलकुल मानी हुई बात है कि माइग्रेशन की वजह से खास तौर से बड़े जो शहर हैं उनकी हालत बहुत खराब है। गांवों से जो लोग आते हैं वह रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं और रफ्ता रफ्ता स्लम्स में रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिये गांवों के लोगों को गांवों में ही रोजगार मिल सके ताकि माइग्रेशन रुके। उधर जो हमारे अब तक के आंकड़े कहते हैं वह यह है कि 27.7 प्रतिशत अरबन एरियाज में पावर्टी है। इसलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही कि जिस तरह से जवाहर रोजगार योजना गांवों के लिए है वह शहरों के लिए तो नहीं हो सकती है लेकिन उसी तरह की दूसरी स्कीम्ज शहरों के लिए बनेगी।

श्री यशवंत सिन्हा : उनके लिए राजीव गांधी योजना शुरू कर दीजिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती मोहसिना किदवई : वह भी शुरू कर देंगे आपको क्या परेशानी है। आपको सब से बड़ी परेशानी यह है कि गरीबों को रोजगार दिला सकें इसकी परेशानी है। **(व्यवधान)** कोई मतलब इससे नहीं है, किसी के नाम से मिले लेकिन रोजगार तो मिले। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आपको उनको जवाब दे दीजिए... **(व्यवधान)**।

श्रीमती मोहसिना किदवई : इनको सिर्फ गरीबों के रोजगार से परेशानी है। **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Don't get diverted in your reply.

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह कह रही हूं कि यह जो गरीबी दूर करने की बातें हैं **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आपने अरबन एरियाज के लिए जो योजना बनाई है वह बताइये, इनकी बातों में मत आइये **(व्यवधान)**

श्रीमती मोहसिना किदवई : चुनाव से जो लोग डरते हैं वह ऐसी बातें करते हैं। हम चुनाव से नहीं डरते हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं अभी प्रधान मंत्री जी ने जवाहर रोजगार योजना जैसी योजना के तहत अरबन पार्टी दूर करने की योजना बनाने के विषय में कहा लेकिन यह बहुत फर्क योजनाएं होंगी। इसके लिए प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनी है एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो इस सवाल में जा रहा है और यह देख रहा है कि किस तरह से कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनके जरिये से अरबन पावर्टी दूर हो सके। कुछ काम हमारी मिनिस्ट्री में भी इसके लिये हो रहा है। मैं समझती हूं कि बहुत जल्दी ऐसी स्कीमें लाएंगे जिससे हम अरबन पावर्टी को दूर कर सकेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, प्रश्न था योजना के लिए और उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : आप सवाल कर लीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, कोई योजना बनी ही नहीं है। लगता है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद नये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयेगी। मेरा प्रश्न यह है कि **(व्यवधान)** यह जो शहरी निर्धन व्यक्ति हैं आपके हिसाब से प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इसका मापदण्ड क्या है, कितनी आय वाले लोग इसकी सीमा के अन्तर्गत आते हैं? **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री **(प्रो० के० के० तिवारी)** : रोज दल बदलते हैं, रोज त्याग-पत्र देते यहां से वहां, मालवीय जी तो सिर्फ यही याद रखते हैं **(व्यवधान)**

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Shri Malaviyaji should give an assurance that the next Prime Minister will also not be from Congress-I or the ex-Congress-I.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मालवीय जी ने अगर यह सवाल पढ़ा होता तो शायद यह सवाल वे न करते लेकिन दिक्कत यह है कि आज बदकिस्मती से अपोजीशन के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है वह परेशानी में रहते हैं। स्कीम्ज आलरेडी बनी हुई है। जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है कि कोई नयी स्कीम पावर्टी दूर करने के लिए आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुरानी स्कीम्ज के बारे में आंकड़े आपके पास हैं। आपको भी मालूम है। यह अरबन एरियाज का प्रश्न है इसमें एक सेल्फ इम्पलायमेंट स्कीम है जिसमें पांच हजार रुपये तक विदाउट एनी गारंटी किसी को भी लोन दिया जा सकता है और लोग ले रहे हैं। उसमें 25 प्रतिशत सबसिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। यह लोन बैंकों के जरिये से तकसीम हो रहे हैं और आपके जिले में भी आया होगा (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा प्रश्न यह था (व्यवधान) मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए मापदण्ड क्या है ?

MR. CHAIRMAN: No, no.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मेरा प्रश्न यह था कि जो निर्धन शहरी व्यक्ति हैं उनकी आय की सीमा क्या है ?

MR. CHAIRMAN: No, please sit down. I am calling Mr. Vishwa Bandhu Gupta.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा प्रश्न यह था कि जो निर्धन शहरी व्यक्ति हैं उनकी आय की सीमा क्या है ?

MR. CHAIRMAN: You don't have to answer that.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: I would like to know from the honourable Minister whether she has considered the point about the National Capital Region, and specially about Delhi, with regard to this 27% poverty people. She has already mentioned that there is a big migration into Delhi. This is probably the highest migration which is taking place towards the Capital. We do not have adequate facilities even now for the people who are living today. But has she made some projections of how much money it will cost to take care of those people who are coming in and whether this 27% is going to increase or decrease over a period of time and for the National Capital Region whether she has made some specific plans so that the poverty situation in this area is taken care of.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति महोदय, नेशनल कैपिटल रीजन का बिल्कुल अलग सवाल है जो दिल्ली के कन्जेशन को दूर करने के लिए और दिल्ली के बाहर ऐसी... (व्यवधान)

श्री सभापति : इसके लिए कोई स्पेशल रोजगार योजना बना रही है क्या, यह पूछ रहे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : वही तो मैंने बताया जो नयी स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं। अर्बन पावर्टी के लिए अभी तक कोई खास स्कीम नहीं थी, सिर्फ यह था कि कुछ स्कीमें जैसे 1984 से शुरू हुई, कुछ 1983 से शुरू हुई थी सेल्फ इम्प्लायमेंट की, लेकिन अब बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश है कि हम अर्बन पावर्टी के लिए भी स्कीम्स बनायें जो बन ई जा रही हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनका ऐलान हो सके।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: While Madam Minister has been eloquently speaking about the launching of new schemes for solving the problem of housing in the urban poor, can I take this opportunity to draw her attention....

MR. CHAIRMAN: Only a supplementary; don't use this as an opportunity to say something else.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Parliamentary niceties are also known to us. You can rely on us. The point is while she is speaking about the programme for the poor in the urban areas and my friend, Mr. Vishwa Bandhu Gupta, as referred to the problem of Delhi, I am also referring to the problem of Delhi but drawing her attention to a place which is near the Jamia University; the place is known as Okhla Bihar. There 5000 houses of the very poor people--and most of them are Muslims were destroyed by using bulldozers on the day before Id. This has taken place when she is boasting of launching new programmes. My supplementary is whether Madam Minister will categorically assure that she will inquire into the problem and see that bulldozers are not used during the emergency times to destroy the poor people in Delhi?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है। आपने जो सवाल उठाया है...

उपसभापति : वह सवाल आप होम मिनिस्ट्री से कीजिए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is under her, Urban Development.

श्रीमती मोहसिना किदवई : डी०डी०ए० की वह जमीन है या एल०जी० करते हैं... (व्यवधान) तो यह सवाल इससे उठता नहीं है लेकिन आपने एक बात कही है मैं पता करवाऊंगी... (व्यवधान) ये अनऑथराइज्ड कालोनी होगी या कुछ हो सकता है।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The Minister in her reply said that the Government accords highest priority to uplifting the urban poor. I would like to know, if this is so, what the Government proposes to do when the State Governments work in exactly the opposite direction. For example, in Maharashtra the State Government in Bombay has de-registered 285 plots which were meant for...

SHRI JAGESH DESAI: No it is distorted.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: There is no notification like this.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am asking a question. Why should they feel disturbed? Let me ask my question.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, he is confused. He is confused in Karnataka and he is confused in Maharashtra. He is totally wrong... (*Interruptions*)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I have a right to ask a question. She may not answer. But let me ask my question...(*Interruptions*)...

SHRI A. G. KULKARNI: He is wrong, Sir... (*Interruptions*)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, it may be in Andhra or it may be in Karnataka. Let him not bring in Maharashtra ...(*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: He is wrong, Sir...(*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: How does this come in, Sir? Where is Karnataka, where is Andhra and where is Mr. Subramanian Swamy? How can this question come in?... (*Interruptions*)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, Mr. Swamy does not have the facts with him... (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I have not yet put my question...(*Interruptions*)...Sir,

you please listen to me...(*Interruptions*)...Sir, you please listen to me.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What do you mean by saying "No"? You cannot say "No"... (*Interruptions*)...I have got every right to ask a question. The question is very important ...(*Interruptions*)... I walk out in protest. You have no right...(*Interruptions*)...You cannot prevent me even from asking a question. Let me ask my question. She may not answer. But let me ask my question...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have every right decide that your supplementary does not arise out of the main question and I rule it out of order...(*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This is not correct...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. Question No. 64. Whatever is spoken without my permission will not go on record. Question No. 64. Mr. Kalmadi... (*Interruptions*)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I walk out in protest...(*Interruptions*)...

(*At this stage, the hon. Member left the Chamber.*)

Wastage of Fruits due to lack of Food Processing Facilities and Technical know how

*64. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large quantity of fruits are being wasted due to the lack of adequate facilities of processing the same and the lack of technical know-how;

(b) if so, the steps proposed to be taken to set up more units both in the public and the private sector; and

(c) whether Government have received any representations for the setting up of food processing units and if so, the action being taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

While no authentic information is available, it is estimated that fruits and vegetables valued at Rs. 3,000 crores are wasted every year due to inadequate post harvest handling as well as absence of linkage with the processors and fresh fruits and vegetables market.

Several measures have been taken from time to time by the Government to facilitate setting up of more units for processing fruits and vegetables. Such measures include the liberalisation of the industrial policy through broad-banding, the inclusion of food processing industries in Appendix-I of the Industrial Policy Statement of 1973, the granting of fiscal concessions etc. Consultancy and technical guidance is also provided for the setting up of units.

A provision has been made under the Plan for financial assistance to State Governments/Cooperative Undertakings for setting up fruit and vegetable processing units.

Representations are received from time to time regarding setting up of food processing units. These are examined by the Ministry of Food Processing Industries and appropriate action is taken.

SHRI SURESH KALMADI; Sir, it is necessary that wherever agro-industries are encouraged, fruits and vegetables should be there in full supply. Recently, some small units have come up--they are high-tech units